* 20th Year
* Issue: 95
* 03.08.2026 (MONDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके की विदेश में पढ़ाई के खर्च पर विवाद, पिता की आय की जांच के लिए आरटीआई कार्यकर्ता ने खोला मोर्चा

नयी दिल्ली ०२/०८ (संवाददाता): कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। सूरत के सूचना अधिकार कार्यकर्ता अमित तिवारी ने अभिजीत दिपके के पिता की विज़ीय स्थिति की जांच करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र सरकार के एक सेवानिवृज़ कर्मचारी होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की विदेशों में उच्च शिक्षा का खर्च कैसे उठाया। इसके अलावा, आरटीआई कार्यकर्ता ने निर्वाचन आयोगऔर टैज़्स अधिकारियों को पत्र लिखकर उस 1 करोड़ रुपये के लीगल डिफेंस फंड की जांच करने की भी मांग की है, जिसकी घोषणा वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिज़्बल ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों के लिए की थी। आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने सीजेपी की

आधिकारिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि ज़्या कोई गैर-पंजीकृत संस्था राजनीतिक दल के नाम पर फंड प्राप्त कर सकती है? अमित तिवारी का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक गैर-पंजीकृत संस्था है, लेकिन यह एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है। अगर इसके लिए 1 करोड़ रुपये का लीगल डिफेंस फंड देने का वादा किया गया है, तो चुनाव आयोग को यह जांच करनी चाहिए कि ज़्या सीजेपी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत है या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि यह संस्था पंजीकृत नहीं है, तो राजनीतिक दल के नाम पर इसका संचालन करना और फंड या डोनेशन जुटाना जांच के दायरे में आना चाहिए।

यह विवाद तब और बढ़ गया जब तिवारी ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का रुख किया। उन्होंने मांग की है कि टैज़्स अधिकारी इस बात की गहराई से जांच करें कि वरिष्ठ वकील कपिल सिज़्बल द्वारा इस लीगल डिफेंस फंड में दिए जाने वाले योगदान पर जीएसटी लागू होगा या नहीं। हाल ही में नीट पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरज़्तार किया था। इन प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता देने के लिए सीजेपी ने एक फंड बनाया था, जिसमें सोमवार को राज्यसभा सांसद कपिल सिज़्बल ने 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था। इसी घोषणा के बाद पूरा मामला कानूनी और विज़ीय जांच के दायरे में आ गया है। इस मामले में प्रमुख रूप से तीन मांगें उठाई गई हैं- अभिजीत दिपके के पिता के आय स्रोतों की जांच हो कि उन्होंने बेटे की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया। बिना रजिस्ट्रेशन पार्टी के रूप में काम करने और फंड जुटाने पर चुनाव आयोग दखल दे। कपिल सिज़्बल द्वारा घोषित 1 करोड़ रुपये के सहायता फंड पर जीएसटी नियमों के तहत जांच की जाए। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत करने वाले 30 वर्षीय अभिजीत दिपके इस समय काफी चर्चा में हैं। दरअसल यह कोई औपचारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक व्यंग्य वाला ऑनलाइन अभियान था जो देखते ही देखते फेमस हो गया। शुरुआत के महज 5 दिनों में ही इंस्टाग्राम पर इसके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए।

अभिजीत दिपके ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पज़्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है। फिलहाल वह किसी नौकरी में नहीं हैं और बोस्टन से भारत लौटते ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। दिल्ली में हुए बड़े प्रदर्शन के बाद अब उनके अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के खर्च पर सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर यह आरटीआई दायर की गई है।

पीएम मोदी ने शुरु किया विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा, एक करोड़ युवाओं ने ली शपथ

नयी दिल्ली ०२/०८ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉल के जरिए 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद देश के युवाओं को नशे के खिलाफ एक साथ लाना है, ताकि भारत को नशा मुक्त बनाया जा सके और देश तरक्की कर सके।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए युवाओं का नशे से दूर रहना और सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, आप सभी इस बड़े अभियान के लीडर हैं और आपने मेरे भरोसे को और मजबूत किया है। पीएम मोदी ने युवाओं से आगे आकर इस अभियान से जुड़ने और अपने इलाकों में लोगों को जागरूक करने की अपील की।

यह अभियान आम लोगों और युवाओं के जुड़ने से शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत में देश भर में करीब 10,000 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम हुए, जहां 1 करोड़ (10 मिलियन) से ज्यादा युवाओं ने नशा न करने की कसम खाई।

सरकार की योजना के मुताबिक, इस अभियान के तहत हर रविवार पूरे देश में अलग-अलग कार्यक्रम किए जाएंगे।

इनमें खेल, पैदल यात्रा, योग, नाटक, रैली और चित्र बनाने जैसी प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इस अभियान में बेहतरीन काम करने वाले युवाओं और संस्थाओं को 50वें, 75वें और 100वें हज़्ते में सज़्मानित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि नशा मुक्त युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। इस अभियान का मकसद युवाओं को सेहतमंद और जिज़्मेदार नागरिक बनाना है।

आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर मायावती की बड़ी कार्रवाई, बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया

नयी दिल्ली ०२/०८ (संवाददाता): उज़्र प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी में अनुशासन तोड़ने के आरोप में उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अशोक सिद्धार्थ मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद के ससुर हैं। मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज़्स पर पोस्ट करके इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव के दौरान पार्टी टिकट के बंटवारे में मनमानी और नियम तोड़ने की वजह से अशोक सिद्धार्थ को निकाला गया था। हालांकि, बाद में इस शर्त पर उन्हें वापस लिया गया था कि वे ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे।

उन्हें यूपी से दूर रखकर सिर्फ दूसरे राज्यों में पार्टी का काम संभालने की जिज़्मेदारी दी गई थी। मायावती ने आगे लिखा कि इसके बावजूद अशोक सिद्धार्थ ने अपनी जिज़्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लगातार उनके खिलाफ शिकायतें आती रहीं। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी जब उन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया, तो उन्हें सभी जिज़्मेदारियों से हटा दिया गया था। मायावती ने कहा कि इसके बाद भी यूपी की राजनीति में उनकी वापसी को लेकर जानबूझकर गलतफहमी फैलाई जा रही थी। यह सब आने वाले यूपी चुनाव के लिए चलाए जा रहे अभियान को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। इसलिए पार्टी के हित में अशोक सिद्धार्थ को तुरंत प्रभाव से बाहर कर दिया गया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि अब उन्हें आगे कभी भी पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा।

आंध्रप्रदेश में गोदावरी नदी का जलस्तर घटा, बैराज पर पानी का भारी प्रवाह जारी

अमरावती ०२/०८ (संवाददाता): दो अगस्त आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) ने रविवार को कहा कि भद्राचलम में गोदावरी नदी का जलस्तर घटने लगा है और वहां से दूसरे स्तर की चेतावनी को वापस ले लिया गया है। हालांकि, दौलेश्वरम बैराज पर अब भी भारी मात्रा में बाढ़ का पानी प्रवाहित हो रहा है।

प्राधिकरण के अनुसार, भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर 47.9 फुट, कुनावरम में 21.5 मीटर और पोलावरम में 13.3 मीटर दर्ज किया गया। वहीं, दौलेश्वरम बैराज पर पानी का प्रवाह और निकास 14.6 लाख ज़्यूसेक दर्ज किया गया। दौलेश्वरम, पूर्वी गोदावरी जिले के राजमुंदरी के निकट स्थित है। एपीएसडीएमए के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "भद्राचलम में गोदावरी नदी में बाढ़ का प्रवाह कम हो रहा है और वहां से दूसरे स्तर की चेतावनी वापस ले ली गयी है। हालांकि, दौलेश्वरम बैराज पर अब भी भारी मात्रा में बाढ़ का पानी बह रहा है।" उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उफनते नालों और जलमग्न पुलियों को पार करने का प्रयास न करें तथा राहत एवं बचाव कार्य में लगे अधिकारियों का सहयोग करें। जैन ने लोगों को यह भी चेतावनी दी कि वर्तमान बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गोदावरी नदी में यात्रा, स्नान, तैराकी या मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों से बचें, ज़्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में ये गतिविधियां अत्यंत जोखिमपूर्ण हैं।

राहुल गांधी ने फ्रेंडशिप डे पर खुद को बताया छात्र, युवाओं के लिए साझा किया खास संदेश

नयी दिल्ली ०२/०८ (संवाददाता): फ्रेंडशिप डे के मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के युवाओं के लिए एक खास मैसेज शेयर किया। उन्होंने सभी को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दीं और लिखा कि वह आज भी खुद को एक छात्र ही मानते हैं और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने दोस्ती को जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता बताते हुए कहा कि प्यार, भरोसा और एक-दूसरे से सीखते रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, अभी भी एक विद्यार्थी हूं, हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। आज का सबक आज मित्रता दिवस है। सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार। आपको बता दें

कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई छात्रों और युवाओं से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी थीं। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये दोनों देश के युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये नेता भारत का बीता हुआ कल हैं और उन्हें सोचना चाहिए कि वे देश के आने वाले भविष्य के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने देश भर में कई युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराए जाने के लिए भी सरकार को जिज़्मेदार ठहराया। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, राजद और समाजवादी पार्टी जैसी बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी अलग-अलग राज्यों में छात्रों पर दर्ज मुकदमों का कड़ा विरोध किया।

पश्चिम बंगाल में जनगणना २०२७ की तैयारी तेज

कोलकाता ०२/०८ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल के मुज़्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को 2027 की जनगणना प्रक्रिया के लिए %सेल्फ़-एन्यूमरेशन% (खुद जानकारी दर्ज करने) की प्रक्रिया शुरू की। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुज़्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ज़ोर दिया कि भारत के जनगणना प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आदेशों को लागू करना पश्चिम बंगाल सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि सेल्फ़-एन्यूमरेशनकी प्रक्रिया एक संवैधानिक ज़िज़्मेदारी है जिसका पालन पूरे देश में किया जा रहा है, न कि सिर्फ़ पश्चिम बंगाल में। अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार अलग से कुछ नहीं करेगी। भारत के जनगणना प्राधिकरण द्वारा जारी गाइडलाइंस और निर्देशों को लागू करना हमारा कर्तव्य है। यह एक संवैधानिक ज़िज़्मेदारी है जिसका पालन पूरे देश में किया जा रहा है, न कि सिर्फ़ पश्चिम बंगाल में। राज्य के लिए जनगणना की वेबसाइट पर 1 अगस्त से 15 अगस्त तक खुद से जानकारी भरने (सेल्फ़-एन्यूमरेशन) की सुविधा उपलज़्ध होगी। इस बीच, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 का पहला चरण पूरा हो चुका है, जबकि तमिलनाडु और त्रिपुरा में शुक्रवार को पहले चरण के तहत हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के लिए सेल्फ़-एन्यूमरेशन की सुविधा शुरू हुई, जिससे इन दोनों राज्यों में जनगणना का काम शुरू हो गया। जनगणना 2027 का पहला चरण 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो गया है-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छज़्ीसगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जज़्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उज़्र प्रदेश और उज़्राखंड घर की लिस्टिंग और आवास जनगणना चरण के दौरान, आवास की स्थिति, परिवार के विवरण, सुविधाओं और संपज़ि के बारे में जानकारी एक तय प्रश्नावली के माध्यम से इकट्ठा की गई, जिसमें 33 अधिसूचित सवाल शामिल थे। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत इकट्ठा की गई सभी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहती है।

इंस्टाग्राम पर मुलाकात और फिर देश विरोधी साजिश, एसटीएफ की गिरफ्त में हमीम मंडल और उसकी गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार

नयी दिल्ली ०२/०८ (संवाददाता): स्पेशल टास्क फॉर्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। पश्चिम बंगाल में पकड़े गए जैश-ए-मोहज़्मद के संदिग्ध आतंकी हमिम मंडल ने ुज़्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। हमिम को दो दिन पहले पूर्वी बर्धमान जिले से पकड़ा गया था। पुलिस अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि हमिम को मुज़्यमंत्री की गतिविधियों पर नज़र रखने और ऐसी जगहों की जानकारी जुटाने को कहा गया था, जहाँ मुज़्यमंत्री बिना सुरक्षा के हो सकते हैं। एसटीएफ

के मुताबिक, पाकिस्तान में बैठे आका चाहते थे कि हमिम पुलिस की वर्दी पहनकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे सीजेपी के छात्र प्रदर्शन में घुसे। उसका मकसद वहां भारी गड़बड़ी और अशांति फैलाना था। मामले में हमिम की प्रेमिका अर्पिता सरकार को भी झारखंड से गिरज़्तार किया गया है। ये दोनों राज्य के मंत्री उमेश राय के बेटे को अपने जाल में फंसाकर अगवा करने और उनके परिवार से पैसे वसूलने की योजना बना रहे थे। अर्पिता नेताओं समेत कई बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाकर जानकारी हासिल करती थी और हमिम तक पहुंचाती थी। उसके व्हाट्सएप चैट से पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत मिले हैं।

पुलिस को इनके पास से ब्रिटेन और मैज़्सिको के अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड मिले हैं। आशंका है कि इनका इस्तेमाल गुप्त बातचीत के लिए किया जाता था। जांच में सामने आया है कि ये दोनों शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर काम कर रहे थे। यह गैंग लोगों को भड़काने, आतंकी नेटवर्क में भर्ती करने और नशे के व्यापार से आतंकवाद फैलाने जैसे कामों में शामिल है। हमिम और अर्पिता की मुलाकात चार साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। अर्पिता के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करते हुए ही स्ञस्न हमिम तक पहुंचने में कामयाब रही। फिलहाल अदालत ने हमिम को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े बाकी लोगों का पता लगाने में जुटी है।

विविध समाचार

पटना एसएसपी पर पीके का हमला, सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रही है पुलिस, गुंडागर्दी का आरोप

पटना ०२/०८ (संवाददाता): जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (स्स्क्क) पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है। किशोर, जो उपचुनाव में पार्टी के उज़्मीदवार भी हैं, ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने पिछले तीन दिनों के चुनावी दौर में सख़्त रवैया अपनाया, वोटरों को डराया-धमकाया, राजनीतिक नेताओं को ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से हिरासत में लिया और एक ख़ास राजनीतिक पार्टी के पक्ष में काम किया। मुज़्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने के बाद इन चिंताओं पर बात करते हुए किशोर ने कहा कि हमने पटना स्स्क्क के खिलाफ लिखित सबूतों के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत चुनाव के दौरान पिछले तीन दिनों में पुलिस के व्यवहार को

लेकर है - खासकर उनके कामों, वोटरों को डराने-धमकाने, राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लेने और एक खास पार्टी के पक्ष में पुलिस की कार्रवाई को लेकर। उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने शिकायत स्वीकार कर ली है और औपचारिक जांच का भरोसा दिया है, साथ ही जांच के नतीजों के आधार पर सज़्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। किशोर ने चेतावनी दी कि अगर स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इस मामले को दिल्ली में चुनाव आयोग और ज़रूरत पड़ने पर अदालतों तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में पटना के स्स्क्क या पुलिस के किसी भी अधिकारी को बिहार में लोकतंत्र को कमज़ोर करने और अपने एजेंडे के हिसाब से प्रक्रिया में हेर-फेर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने पुलिस पर सज़ाधारी पार्टी के साथ मिलकर वोटरों को डरा-धमकाकर और उन्हें दबाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। किशोर ने कहा कि पटना, बज़्तियारपुर और पूरे बिहार में आपराधिक तत्वों ने पुलिस के साथ मिलकर जिस तरह की गुंडागर्दी की है, उसे जनता ने देखा है।

यह विवाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार और वोटिंग के दौरान चुनाव में व्यवस्थित दखल, वोटरों को दबाने और राजनीतिक नेताओं को खास तौर पर हिरासत में लेने के आरोपों से पैदा हुआ है। शुक्रवार को किशोर ने पत्रकारों को बताया कि जन सुराज के नेताओं को बिना किसी औपचारिक गिरज़्तारी रिकॉर्ड के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में हिरासत में रखा गया और उन्हें बिना जानकारी दिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने बताया, पुलिस ने कल शाम से देर रात तक जन सुराज के 16 से ज़्यादा नेताओं को परेशान किया। उन्हें तथाकथित तौर पर गिरज़्तार किया गया था, हालांकि तकनीकी रूप से कागज़ों पर कोई औपचारिक गिरज़्तारी दर्ज नहीं की गई; उन्हें हिरासत में लिया गया और अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में रखा गया।

पीएम मोदी के माफी विडियो पर दिपके का पलटवार: क्या आप सिर्फ रील्स के लिए माफ करेंगे या केस भी वापस लेंगे

नयी दिल्ली ०२/०८ (संवाददाता): जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशज़्दों का प्रयोग करने वाले छात्रों को क्षमा करने की अपील पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया है कि ज़्या करुणा के इस संदेश के साथ-साथ उनके खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के सेल्फी वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए दिपके ने सवाल उठाया कि ज़्या करुणा की यह अपील कार्रवाई में तज़्दील होगी।

उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि दोस्त, सिर्फ रील पर ही माफ करोगे या केस भी वापस लोगे?

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम और ङ्ग अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में ये बातें कहीं। यह संदेश दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के

दौरान नोएडा के एक 15 साल के प्रदर्शनकारी के खिलाफ़ उनके बारे में अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किए जाने के बाद आया। इस विवाद पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मेरा मन आपसे बात करने का कर रहा है। देश और दुनिया ने देखा है कि जंतर-मंतर पर ज़्या हुआ। कुछ शरारती बच्चों ने बहुत भद्दी और गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसे शज़्दों का इस्तेमाल किया जो किसी भी सज़्य समाज के लिए ठीक नहीं हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से अपशज़्द कहे गए, और मेरी दिवंगत माँ के बारे में भी अपशज़्द कहे गए। यह सचमुच बहुत ही शर्मनाक नज़ारा था।

इस घटना पर लोगों के गुस्से को समझते हुए, प्रधानमंत्री ने ज़ोर दिया कि जो युवा गलती करते हैं, उन्हें हमेशा के लिए दोषी ठहराने के बजाय सही रास्ता दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र सही रास्ते से भटक गए थे, लेकिन उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने लंबी कानूनी कार्रवाई और समाज से अलग-थलग करने के खिलाफ भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें सज़ा देना, अदालती कार्यवाही में

स्पीकर से उपर समझने की बीमारी का इलाज नहीं, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रिजिजू का पलटवार

नयी दिल्ली ०२/०८ (संवाददाता): संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर अशांत होने और जनता की इच्छा के विरुद्ध जाने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि विपक्ष अध्यक्ष की शक्ति को अपने लिए हथियाने की कोशिश कर रहा है। मतघोषणा के बीच विपक्षी सांसदों पर कटाक्ष करते हुए मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी के पूर्व बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई सदन में खुद को अध्यक्ष से ऊपर समझता है तो उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। रिजिजू ने सदन में कहा कि संविधान और

सदन के नियमों को देखें तो किसी ने भी अध्यक्ष के किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दी है। उस दिन मैं इस बात से नाराज था कि विपक्षी सांसद ने कहा था कि %मुझे संसद में बोलने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है%, यह रिकॉर्ड में है। %संसद में बोलना मेरा अधिकार है%, हमारे विपक्ष के नेता ने यह कहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने यह ज़्यों नहीं समझाया कि इस सदन में प्रधानमंत्री, मंत्री, विपक्ष के नेता मौजूद हो सकते हैं लेकिन बोलने के लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है।

मंत्री ने आगे कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते और फिर कहते हैं कि आपका माइक्रोफोन बंद है।

बिना अनुमति के, अगर आप खुद को स्पीकर से ऊपर समझते हैं, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका न देकर अध्यक्ष पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रति पक्षपात करने के आरोपों के बारे में बोलते हुए, रिजिजू ने कहा कि स्पष्ट नियम मौजूद हैं जिनके तहत सदन में कोई भी सदस्य बोल सकता है और अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर सकता है।उन्होंने कहा कि एक और बात, नियम 115 (ए) में यह प्रावधान है कि जब भी सांसद बोलने का नोटिस देते हैं, तो सभी दल ऐसा नोटिस देते हैं। यहां तक कि अगर कोई सदस्य स्वयं नोटिस देता है, तो वह बोल सकता है। यदि कोई अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो वह अपना हाथ उठाकर ध्यान आकर्षित कर सकता है। नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने का मौका दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी हैं, जिनका उल्लेख कार्यविधि और कार्यवाही के नियमों में नहीं है, जैसे कि जब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करेगा। इसीलिए यह परंपरा इतना बड़ा मुद्दा है।

लोकसभा में विपक्ष पर भड़के शिवराज सिंह चौहान, कहा-ऐसी राजनीति पर शर्म आती है

नयी दिल्ली ०२/०८ (संवाददाता): केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष द्वारा की गई नारेबाजी की कड़ी आलोचना की। चौहान जब केंद्र सरकार की किसान योजनाओं से संबंधित प्रश्नों का उज़र दे रहे थे, तब विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। इंडिया ज़्लॉक के सांसदों ने कथित वोट चोरी का विरोध किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिवराज चौहान ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों से संबंधित हैं। किसान और देश सुनना चाहते हैं, लेकिन वे (विपक्ष) नहीं चाहते कि देश सुने। विपक्ष की ऐसी राजनीति शर्मनाक है।

तेल बीज मिशन और झारखंड में कृषि सहायता से संबंधित एक प्रश्न का उज़र देते हुए उन्होंने कहा कि फलों और सज़्जियों के उत्पादन के लिए हमने एमआईडीएच योजना शुरू की है और झारखंड सरकार को बागवानी के लिए भी सहायता मिल रही है। हम पॉली हाउस,

ग्रीनहाउस और सिंचाई के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं। इसी बीच, कांग्रेस सांसद मोहज़्मद जावेद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 50 से अधिक सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद अध्यक्ष पद पर आसीन भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद को अवकाश दे दिया।

जगदंबिका पाल ने कहा कि बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है और सांसदों से प्रस्ताव पर कायम रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष ने अनुमति और प्रक्रिया में उदारता दिखाई है। प्रस्ताव पर मतदान से पहले, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में उपसभापति की नियुक्ति पर बहस छेड़ दी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने पिछले कई वर्षों से उपसभापति की नियुक्ति नहीं की है, जिससे संवैधानिक शून्य पैदा हो गया है। जगदंबिका पाल के अधिकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आपकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ने की थी। उन्होंने आगे कहा कि सदन को एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो प्रस्ताव पर बहस के दौरान कार्यवाही की अध्यक्षता करेगा।

बंगाल वोटर लिस्ट पर संग्राम, भाजपा का टीएमसी पर आरोप-घुसपैठियों के सहारे जीतना चाहते हैं चुनाव

कोलकाता ०२/०८ (संवाददाता): बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय साराओगी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक अधिकार है और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर फर्जी वोटों से चुनाव में हेरफेर करने का आरोप लगाया।

एएनआई से बात करते हुए साराओगी ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया संचालित करने का संवैधानिक अधिकार है और चेतावनी दी कि बंगाल के संसाधनों पर घुसपैठियों या फर्जी मतदाताओं का नहीं, बल्कि बंगाल की जनता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है।

एसआईआर प्रक्रिया संचालित करना उनका अधिकार है। ये लोग ज़्या चाहते हैं? ज़्या वे बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं, घुसपैठियों, मृतकों और दोहरी प्रविष्टियों वाले फर्जी वोटों का इस्तेमाल करके जीतना

चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। बंगाल के संसाधनों पर घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का नहीं, बल्कि बंगाल की जनता का अधिकार है। साराओगी ने पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी की भी आलोचना करते हुए उन पर सांप्रदायिक और अहंकारी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए ममता बनर्जी की सांप्रदायिक और अहंकारी मानसिकता... लोग इसे देख रहे हैं... आने वाले समय में बंगाल की जनता टीएमसी का सफाया कर देगी और भाजपा की सरकार बनेगी।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को मतदाता सूची के एसआईआर (स्ढ्ढक्र) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए जाने का आरोप लगाया। पार्टी के विरोध प्रदर्शन के समापन पर बोलते हुए बनर्जी ने कहा कि मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछे गए कई सवालों के जवाब नहीं मिले और उन्होंने उसी दिन इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का जिक्र किया। बनर्जी ने कहा ज्ञानेश कुमार से कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने सभी के जवाब नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर मामले की सुनवाई की। मतदाताओं के नाम एकतरफा रूप से हटाए जाने के हमारे संदेह को हमने कोर्ट के सामने उठाया था।

कतर में फंसे 500 से अधिक भारतीयों की वतन वापसी

नयी दिल्ली ०२/०८ (संवाददाता): भारतीय दूतावास ने बुधवार को बताया कि कतर में फंसे 500 से अधिक भारतीयों को नयी दिल्ली और अन्य स्थानों पर पहुंचाया गया है। दूतावास ने पश्चिम एशियाई देश में अब भी फंसे लोगों को किसी भी अज्ञात वस्तु, मलबे या टुकड़ों के पास जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। कतर स्थित भारतीय दूतावास ने 'एज़्स' पर एक परामर्श में कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच कतर एयरवेज बृहस्पतिवार को भारत के लिए दो उड़ानें संचालित करने वाली है। दूतावास ने कहा, कतर में फंसे 500 से अधिक भारतीय 11 मार्च को कतर एयरवेज की उड़ानों से नयी दिल्ली और अन्य गंतव्यों के लिए रवाना हुए।

संघर्ष के कारण उड़ानें रद्द होने से दुबई में फंसे ओडिशा के 35 पर्यटक बुधवार को सुरक्षित घर लौट आए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुज़्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, फंसे हुए पर्यटकों में से नौ पर्यटक सात मार्च को केरल के कोच्चि होते हुए भुवनेश्वर लौट आए।

बयान में बताया गया कि बाकी पर्यटक आठ मार्च को मुंबई होते हुए 'एअर इंडिया एज़्सप्रेस' की विशेष उड़ान से राज्य की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस बात पर चिंता जताई कि क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में ओडिशा के कई लोग फंसे हुए हैं।

मुज़्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि माझी ने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुज़्य सचिव अनु गर्ग को स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और उडिया लोगों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। वहीं, विपक्षी दलों ने विधानसभा में ओडिशा सरकार पर खाड़ी देशों में जारी संघर्ष के बीच फंसे राज्य के लोगों के प्रति कोई चिंता न दिखाने का बुधवार को आरोप लगाया।

मुज़्य सचेतक प्रमिला मलिक और प्रताप केशरी देब द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में इस मुद्दे पर बहस हुई।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की जज पर उठाए सवाल, मांगा केस ट्रांसफर

नयी दिल्ली ०२/०८ (संवाददाता): दिल्ली उच्च न्यायालय के मुज़्य न्यायाधीश के समक्ष एक अज़्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें आबकारी नीति मामले से संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ से किसी अन्य उपयुक्त पीठ में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। यह अज़्यावेदन अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर किया गया है, जो इस मामले में प्रतिवादी संज़्या 18 के रूप में नामित हैं। 11 मार्च को दिए गए अज़्यावेदन में केजरीवाल ने मुज़्य न्यायाधीश से, मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में, न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्षता और तटस्थता में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए मामले को प्रशासनिक रूप से स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। अज़्यावेदन में केंद्रीय जांच ज़्यूरो द्वारा कथित आबकारी नीति मामले में आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका की पहली सुनवाई के दौरान हुए कुछ घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की गई है। इसमें कहा गया है कि 9 मार्च को पहली सुनवाई में ही न्यायालय ने नोटिस जारी कर प्रथम दृष्टया यह राय दर्ज की कि निचली अदालत का विस्तृत बरी करने का आदेश त्रुटिपूर्ण था, जबकि बरी किए गए आरोपियों की सुनवाई अभी तक नहीं हुई थी। अज़्यावेदन के अनुसार, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के तहत कार्यवाही को प्रभावित करने वाले अंतरिम निर्देश भी जारी किए, जबकि एजेंसी पुनरीक्षण याचिका में पक्षकार नहीं थी। इसमें कहा गया है कि सीबीआई द्वारा दायर याचिका में ईडी की कार्यवाही से संबंधित राहत की मांग नहीं की गई थी और प्रारंभिक चरण में इसे एकतरफा रूप से प्रदान किया गया था। याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि ऐसे निर्देशों के व्यापक परिणाम होंगे ज़्योंकि ईडी का मामला सीबीआई द्वारा जांचे गए मूल अपराध पर आधारित है। इसमें तर्क दिया गया है कि ईडी की कार्यवाही को पुनरीक्षण याचिका के परिणाम से जोड़ना, बिना किसी प्रार्थना के और बरी किए गए आरोपियों की सुनवाई किए बिना, इस मामले में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में आशंकाओं को मजबूत करता है।

विविध समाचार

एक्सपायर होने के बाद भी काम आएंगी ये चीजें

एक्सपायर चीजें भी घर में कई तरह से काम आती है। कई लोग हैं जो खाने-पीने से लेकर दवाई जैसी चीजों के एक्सपायर होने पर इसे फेंक देते हैं।

हर घर में अक्सर खाने–पीने से लेकर मेकअप जैसी कई चीजें एक्सपायर हो जाती है। लेकिन यह प्रोडक्ट इतने ज्यादा महंगे होते है कि इन्हें फेंकने पर बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए आपके लिए हम कुछ ऐसे हेक्स लेकर आए हैं, जिसे जानने के बाद आप कभी एक्सपायर चीजों को फेकेंगी नहीं। क्योंकि आप इसे एक्सपायर होने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपायर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे। कई बार होता है कि आप घर में कई प्रोडक्ट हर दिन यूज नहीं कर पाते। मेकअप के भी ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, जो एक्सपायर होने के बाद आप उसका इस्तेनाल किसी कीमत पर नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए, क्योंकि इससे आपके स्किन पर प्रभाव पड़ सकता है।

- आप इन एक्सपायर प्रोडक्ट से बच्चों के लिए पेंट बॉक्स तैयार कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आप लिपिस्टिक को एक बर्तन में निकाल लें।
- अब आप इसे अच्छे से पीसकर इसमें हल्का पानी मिला लें।
- ध्यान रखें इसका पेस्ट गाढ़ा बनाना है। इसके बाद आप इसे पेंट बॉक्स में डाल सकती हैं।
- फेस पाउडर से भी आप कलर तैयार कर सकते है।
- इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर आप पेंट बॉक्स के लिए क्रीम कलर तैयार कर सकते हैं।

एक्सपायर कफ सिरप का इस तरह करें इस्तेमाल

- एक्सपायर कफ सिरप भले ही आपके सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन यह आपके घर को चमकाने के लिए बेहद काम आएगा। आप कफ सिरप का प्रयोग किचन सिंक और बाथरूम के बेसिन को साफ करने के लिए कर सकते हैं।
- इसके लिए आप कफ सिरप में एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच नमक मिलाकर अच्छे से मिला लें।

- इसके बाद आप इसे बेसिन और सिंक पर डालकर ब्रश की मदद से रगड़ें।
- इसके बाद अच्छे से पानी से धो लें।
- ऐसा करने से बेसिन और सिंक का पीलापन खत्म हो जाएगा।
- यह बेसिन को साफ करने का आसान तरीका है।

एक्सपायर चायपत्ती का इस तरह करें इस्तेमाल

- यह चांदी को चमकाने का आसान तरीका है।
- इसके लिए आपको एक छोटे बर्तन में एक कप पानी लेना है।
- इसमें एक चम्मच चायपत्ती मिलाकर उबाल लें।
- अब गैस बंद करके पानी हलका ठंडा हो जाए, तो इसमें अपनी पायल डालें।
- 10 मिनट तक पानी में पायल को रहने दें।
- इसके बाद पायल को पानी में से निकालकर साफ कपड़े या ब्रश की मदद से रगड़ें।
- ध्यान रखें कि आपको हल्के हाथ से रगड़ना है।
- ऐसा करने से चांदी के पायल पर लगी गंदगी साफ हो जाती है।

सास बनना नहीं है इतना आसान

सास-बहू का रिश्ता सबसे अनोखा माना जाता है। यह रिश्ता प्यार, सम्मान और समझदारी पर टिका होता है, लेकिन कई बार यह चुनौतियों से भी भरा होता है।

एक मां से सास बनना आसान नहीं होता है। इस दौरान कई बदलाव आते हैं। कोई भी नया रिश्ता चुनौतियों और जिम्मेदारियों का एक नया सेट लेकर आता है। सास बनने का मतलब है कि परिवार की गतिशीलता में एक नई भूमिका निभाना। खास बात यह है कि इसे निभाना हर मांओं के लिए चैलेंजिंग होता है। इसी के साथ चलिए रिलेशनशिप एक्सपर्ट आशमीन मुंजाल से इन चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

रिश्तों में संतुलन का डगमगाना

एक नई सास के रूप में कई बार माताएं अपनी बहू से अच्छी तालमेल नहीं बना पाती हैं। हालांकि, ये गलती कई बार बहू के तरफ से भी की जा सकती है। ऐसे में, रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पाता है और दोनों को लड़ाई–झगड़े आदि का शिकार होना पड़ता है।

अपेक्षाओं का अंतर

एक नए रिश्ते के साथ, दोनों तरफ से अपेक्षाओं में बहुत अंतर हो जाता है। हर किसी की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करना कभी–कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मां अपने बेटे के साथ–साथ बहू से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखती है, जो पूरा न होने पर तनाव का कारण बन जाता है।

रीति–रिवाजों में अंतर

इस बात की काफी हद तक संभावना होती है कि परिवार का नया सदस्य चाहे बहू हो या दामाद वे अन्य परंपराओं, मान्यताओं और मूल्यों का पालन करने वाले होंगे। ऐसे में, एक सास के रूप में आपको उनपर बहस करने की जरूरत नहीं है। बल्कि अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए आपको उनके ट्रेडिशन का भी सम्मान करना होगा।

गलतफहमियों का शिकार होना

सास बनने के बाद कई बार महिलाएं अपनी बहू को ठीक से नहीं समझ पाती है या कभी-कभी बहू उन्हें नहीं समझने की कोशिश करती है, जिससे रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में, एक नई सास के रूप में, भ्रम और संघर्षों का सामना करना पड़ता है।

एक सास के रूप में, आपको नए वातावरण का सामना करना मुश्किल हो सकता है; हालांकि, अपनी बहू या दामाद को अपनी बेटी और बेटे की तरह माने। ऐसा करने से हमेशा एक–दूसरे के लिए शांति, प्यार, सम्मान और करुणा बनी रहेगी।

इन तरीके से बनाएं अपने बच्चे को बुक लवर

मोबाइल और इंटरनेट के इस जमाने में बच्चे किताबों से पढ़ाई कम ही करते है। ऐसे में हर पैरेंट्स चाहते है कि उनके बच्चे किताब से पढ़ें, क्योंकि फोन से स्टडी कम और ध्यान इधर-उधर ज्यादा भटकता है।

आज के इस इंटरनेट दौर में बच्चे पढ़ाई के नाम पर लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। इससे दिक्कत ये हो रही है कि स्टडी के अलावा भी बच्चे का दिमाग इधर–उधर भटक जाता है। मोबाइल पर कई ऐसे ऐड आते हैं, जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है और वह उस लिंक पर क्लिक करके दूसरे वेबसाइट या वीडियो को देखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में माता–पिता की परेशानी बढ़ने लगती है। हर पैरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा फोन से नहीं पढ़ पाता है और पढ़ाई के लिए किताब का होना बेहद जरूरी है। पर, बच्चों की किताबों से पढ़ाई की आदत कैसे लगाई जाए, ये आज हर पैरेंट्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। अगर आपका बच्चा भी सिर्फ मोबाइल में लगा होता है और किताबों में कम इंट्रेस्ट दिखाता है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे अपने बच्चों को आप बुक लवर बना सकती हैं। तो चलिए इस बारे में आगे विस्तार से जानते है।

बच्चों के साथ आप भी पढ़ें बुक

एक रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे वही करते हैं, जो आसपास के माहौल से सिखते हैं। ऐसे में अगर आप खुद मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह उनके सामने बुक पढ़कर उन्हें सुनाएं। ऐसा करने से धीरे–धीरे उन्हें भी किताबों में इंट्रेस्ट आएगा और वो बुक पढ़ना शुरू कर देंगे।

बच्चों के अनुसार करें किताबों का चुनाव

बच्चों में किताबों के प्रति इंट्रेस्ट जगाने के लिए जरूरी है कि आप उसके अनुसार ही बुक लाए। यानी बहुत ज्यादा टेक्स्ट किताबें बच्चे नहीं पढ़ पाते है। ऐसे में जरूरी है कि उनके बुक्स में अट्रैक्टिव ग्राफिक्स जरूर शामिल हों। ग्राफिक्स के बहाने ही कम से कम बच्चे बुक्स खोलकर जरूर पढ़ेंगे।

फन करते हुए पढ़ाएं

अगर आप बच्चे पर पढ़ने के लिए ज्यादा प्रेशर डालेंगे, तो वो दबाव में आकर किताबों से दूर हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे फन करते हुए किताबों को पढ़ाएं। इससे उनके अंदर किताब पढ़ने में दिलचस्पी आएगी।

सेट करें रीडिंग टाइम

बच्चों की आदतों में बदलाव लाने में रुटीन का अहम रोल होता है। ऐसे में, अगर आप उनकी रीडिंग टाइम को सेट कर देते हैं, तो वह खेल–कूद के बाद एक समय पर किताब पढ़ने के लिए भी बैठ सकता है। पर, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे के पास बैठे और उन्हें पढ़ाई करते हुए सुनें भी।

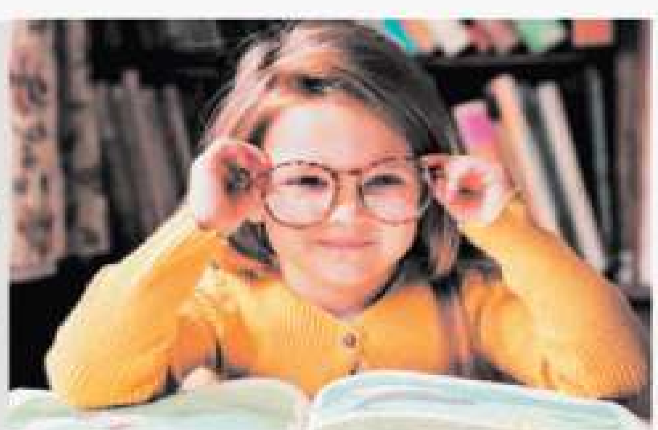

पढ़ने के बाद जल्दी भूल जाता है आपका बच्चा? इस तरीके से हमेशा रहेगा याद

बच्चे खेल–कूद और शैतानी करने में हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पढ़ाई करने को बोल दिया जाए तो एक से बढ़कर एक बहाने बनाना शुरू कर देते है। दरअसल, उन्हें, नई चीजें सीखने और उसे याद रखने में काफी परेशानी होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अमूमन बच्चे पढ़ाई–लिखाई में रुचि नहीं रखते हैं, तो कुछ बच्चे ज्यादा जानकारी एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। बच्चों के इस समस्याओं के कारण स्कूल से काफी कंप्लेन भी पैरेंट्स को झेलने पड़ते है। ऐसे में, माता–पिता को बच्चे की स्टडी और फ्यूचर को लेकर काफी चिंता रहती है। लेकिन अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। यहां ऑक्सफोर्ड की रिसर्च के अनुसार जानेंगे चाइल्ड की मेमरी पावर बढ़ाने का सही तरीका क्या है।

पढ़ाई को बनाएं रोमांचक

ऑक्सफोर्ड की रिसर्च के अनुसार, अगर आपका बच्चा पढ़ा हुआ चीज जल्दी भूल जाता है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाएं। सिर्फ किताबें लेकर रटने से उन्हें कभी कुछ याद नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि टॉपिक को किसी चीज से रिलेट करके उसे समझाएं। इससे लंबे समय तक पढ़ी हुई चीजें याद रहेगा।

पढ़ाने में लें विजुअल का सहारा

बच्चे को अगर स्कूल में कुछ याद करने के लिए वर्क मिला है, तो पैरेंट्स की जिम्मेदारी होती है उसे पढ़ाना। ऐसे में बच्चे को लंबे समय तक टॉपिक याद रखने के लिए आप कुछ क्रिएटिव तरीके का हेल्प ले सकते हैं। दरअसल, ऑक्सफोर्ड रिसर्च के मुताबिक, बच्चों को वीडियो में देखी गई चीजें ज्यादा दिनों तक याद रहता है। इससे माइंड में वीडिओज रह जाती है और बच्चा इसे लंबे समय तक नहीं भूलता है।

छोटे–छोटे पार्ट्स में समझाएं

ऑक्सफोर्ड की रिसर्च के अनुसार, अगर स्टडी मैटेरियल बहुत ज्यादा लंबा है, तो उसे छोटे–छोटे पार्ट्स में बांट दें। बड़े वाक्य या टॉपिक को याद करने में बच्चों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए उन्हें शॉर्ट में समझाएं।

समझाने के बाद बच्चे को बनाएं टीचर

बच्चे को टॉपिक समझाने के बाद उन्हें टेस्ट करने के लिए टीचर बनने को कहें। रिसर्च के अनुसार, बच्चे अगर खुद उन टॉपिक्स के बारे में अपने शब्दों में समझाते हैं, तो समझ लीजिए उन्हें पढ़ा हुआ चीज याद हो गया है। खास बात यह है कि ऐसा करने से बच्चों का मेमोरी पावर भी बढ़ता है।

खास हो आपका वॉर्डरोब

हर किसी की चाहत होती है कि उसका वॉर्डरोब फैशनेबल ड्रेसेज और एसेसरीज से भरा रहे। अपने वॉर्डरोब को फूल करने के चक्कर में लोग अक्सर भूल जाते है कि फैशन का ट्रेंड बदलता रहता है। ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है कि एक टाइमलेस वॉर्डरोब के बारे में सोचा जाए।

फैशन ट्रेंड की भविष्यवाणी थोड़ा मुश्किल काम है। आज जो ट्रेंड है, वह कल होगा या नहीं, इसके बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह भी पूरी तरह से सच नहीं है कि आप लिटेस्ट फैशन को जज न कर सके। वैसे भी कुछ बेसिक आइटम्स की जरूरत हमेशा बनी रहती है। इन्हें अपने वॉर्डरोब में शामिल करके अपने वॉर्डरोब को फैशनेबल बना सकती हैं। आप अपने वॉर्डरोब में कुछ टाइमलेस ड्रेसेज, ज्वैलरी और फुटवियर्स शामिल करें, ये आपके काम आएंगे।

वाइट शर्ट

फैशन डिजाइनर सौमित्र कुमार की मानें, तो वॉर्डरोब के लिए वाइट टेलर्ड शर्ट सबसे जरूरी है। दरअसल, वाइट शर्ट या टॉप के साथ कुछ भी मैच करके पहना जा सकता है। वाइट शर्ट के साथ कोई भी एसेसरीज आसानी से मैच हो जाती हैं। आप चाहें तो वाइट शर्ट में डिफरेंट कट्स, स्टाइलिश स्लीव्स या फंकी कॉलर्स डिजाइन करवा सकती है। वहीं, फैब्रिक में सिल्क, शिफॉन व जॉर्जेट टेक्सचर ट्राई करें। इन फैब्रिक्स में फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और इन्हें हर सीजन में पहना जा सकता है।

शिफ्ट ड्रेसेज

अक्सर लड़कियां किसी ओकेजन को ध्यान में रखकर ड्रेसेज परचेज करती है। यही वजह है कि अगर उन्होंने फॉरमल ओकेजन के लिए ड्रेस ली है, तो वह उसे नाइट पार्टी में पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ऐसे में शिफ्ट ड्रेसेज बेस्ट ऑप्शन है। इन्हें आप डे व नाइट दोनों मौकों पर पहन सकती हैं। दरअसल, एक सिंपल ड्रेस से भी मैजिक क्रिएट किया जा सकता है। जरूरी यह है कि उसे स्मार्टनेस के साथ कैरी किया जाए। शिफ्ट ड्रेसेज पहनने से फेमिनिन लुक तो आता ही है तथा इन्हें कैरी करके आप और भी ज्यादा स्टाइलिश लग सकती हैं।

जैकेट

यदि आप एक ही ड्रेस पहनकर बोर हो गई है तो जैकेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती है। इन दिनों मिलिट्री जैकेट ट्रेंड में है। इन्हें आप सॉलिड कलर्स में ले सकती हैं। इससे आपको क्लासिक लुक मिलेगा। यदि आप नाइट आउट पर जा रही हैं तो शाइनी जैकेट बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप लेगिंग्स के साथ मैच करके पहन सकती हैं। इससे आपको पूरा पार्टी लुक मिलेगा और आप काफी ग्लैमरस लगेंगी।

ब्लैक ड्रेसेज

कोई भी वॉर्डरोब ब्लैक ड्रेसेज के बिना कम्प्लीट नहीं होता है। इसे किसी भी ओकेजन पर पहना जा सकता है। चाहे आप स्लिम दिखना चाहती हो या अपने लुक में विंटेज चाहती हों, ब्लैक ड्रेस के साथ हल्की–फुल्की ज्वैलरी कैरी करें। इसका मिक्स एंड मैच स्टाइल से खुद को डिफरेंट लुक दिया जा सकता है। ब्लैक ड्रेस के साथ सिल्वर जूलरी बहुत फबती है। आप इनके साथ अपने वॉर्डरोब में ट्रेंडी शूज भी शामिल कर सकती हैं। इनके कलर सीजन के मुताबिक चुनें। इन्हें आप सिल्वर, गोल्ड और प्लेन ब्लैक में चुन सकती हैं। यह आपकी पर्सनैलिटी पर खूब फबेगा।

जींस

हर किसी के पास एक पेयर जींस होना लाजिमी है, लेकिन उसका फिट होना भी बहुत जरूरी है। फैशन डिजाइनर सौम्या अरोड़ा कहती हैं, जींस हर ऐज में और हर ओकेजन में पहन सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि जींस ब्रांडेड ही हो। आप जींस के साथ खूब एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं। अगर आप कैजुअल आउटिंग पर जा रही हैं, तो इसके साथ बैगी टी–शर्ट व स्नीकर्स पहन सकती हैं। यदि आप को पार्टी में जाना है तो जींस के साथ स्टाइलिश टॉप और हाई हील्स ट्राई कर सकती हैं। यह ध्यान रखें कि जींस की क्वॉलिटी अच्छी हो।

पर्ल

जिस तरह डायमंड हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है। वैसे ही पर्ल भी कभी फैशन से आउटडेटेड नहीं होते है। आप एसेसरीज में पर्ल नेकलेस या ब्रैसलेट्स जरूर रखें। इन्हें आप हर तरह के आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकती हैं। अगर आप रियल पर्ल नेकलेस पसंद नहीं करती है तो फेक नेकलेस खरीद सकती हैं।

कलिंग समाचार

सोमवार 03 अगस्त 2026

नेहरू और बाबरी मस्जिद

देश के पहले प्रधानमंत्री पं.नेहरू का खौफ समूची भाजपा पर इस कदर तारी है कि उसे नित नए झूठ अपने बचाव में गढ़ने पड़ते हैं। नेहरू की जीवनशैली, उनकी महिला मित्र, खान-पान की आदतों को लेकर संघ ने खूब झूठ फैलाया, फिर भाजपा ने इस काम को आगे बढ़ाया। सोशल मीडिया आने के बाद इस दुष्प्रचार में और तेजी आई, फिर भी नेहरू के नाम पर कोई दाग भाजपा नहीं लगा पाई। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में घूमते रहते हैं, अपने नाम की माला जपवाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बसे जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिटा पाते। पुरानी पीढ़ी के नेताओं की बात छोड़ दें, नयी पीढ़ी के वैश्विक नेता भी नेहरू-गांधी को ही याद करते हैं। कोई सावरकर, गोलवलकर से प्रेरित होने की बात नहीं कहता। यही पीड़ा संघ को सालती है कि उनके प्रातस्मरणीय पुरुषों के नामलेवा दुनिया में क्यों नहीं हैं। यह डर और पीड़ा तो लाइलाज है, लिहाजा बेसिरपैर की बातों से भाजपा अपना मन बहलाने में लगी है। ऐसी ही एक बेतुकी बात का उदाहरण पेश किया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च के दौरान राजनाथ सिंह ने दावा किया कि, पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करना चाहते थे। यदि किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो वह सरदार वल्लभभाई पटेल थे। राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए बताया कि पटेल ने इसे सार्वजनिक दान से ही कराया, जिसमें 30 लाख रुपये जुटाए गए, लेकिन कोई सरकारी धन नहीं लगा। इसके बाद नेहरू-पटेल की परंपरा में जबरन नरेन्द्र मोदी को जोड़ने की कोशिश में राजनाथ सिंह ने कहा कि सोमनाथ की तरह, अयोध्या में मौजूदा राम मंदिर का निर्माण भी पूरी तरह जनता के योगदान से हो रहा है। सिंह ने नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें पटेल की विरासत को मिटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पुनर्स्थापित किया। राजनाथ सिंह का यह भाषण न केवल घोर निंदा के योग्य है, बल्कि सिरे से झूठा होने के कारण गहन चिंताजनक भी है। जब देश के शीर्ष पदों पर बैठे लोग झूठे बयान देने लगें तो सत्यमेव जयते के ध्येय वाक्य की रक्षा कैसे होगी। ऐतिहासिक दस्तावेज के मुताबिक बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने कराया था। यह मस्जिद पहले से मौजूद थी और 1947 से 1964 तक नेहरू के कार्यकाल में इसके नए निर्माण का कोई प्रस्ताव या प्रमाण नहीं मिलता। सब जानते हैं कि पं. नेहरू सरकारी धन के दुरुपयोग के स त खिलाफ थे। वे खुद अपना खर्च भी बड़ी किफायत से चलाते थे और ऐसे कई प्रसंग हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका स्टाफ अक्सर उनसे उनके पैसे ही बचा कर रखता था, क्योंकि वे जरूरतमंदों को दे देते थे और खुद उनके पास फिर पैसे नहीं बचते थे। नेहरू हर तरह की धर्मांधता और सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वे धार्मिक आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के भी खिलाफ थे। बल्कि उनके हिसाब से औद्योगिक कारखाने ही आधुनिक भारत के तीर्थ हैं। अगर नेहरू के बाद की तमाम सरकारें इसी सिद्धांत पर चलती तो आज भारत विकास में चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों को टक्कर देता। लेकिन धर्म के नाम पर राजनैतिक समझौता करने की नीति ने देश को पीछे ही रखा। नेहरू जैसी दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति उनके बाद के प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाए। नेहरू सरकार को धार्मिक कार्यों में संलगन होने या जनता के धन को धार्मिक स्थलों में इस्तेमाल करने के स त खिलाफ थे। इसलिए 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान नेहरू ने सरकारी फंडिंग का विरोध किया था, जिसे पटेल ने सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से पूरा कराया था। सरदार पटेल भी नेहरू जैसे ही सिद्धांतवादी थे। उन्होंने कहा था कि जब तक वह ज़िंदा हैं सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खज़ाने से एक पैसा नहीं देंगे। तो भारत के संविधान और नेहरू-पटेल की नीतियों में कोई भेद नहीं था। जबकि आज की सरकार इसके बिल्कुल उलट काम कर रही है।

श्रमिक असंतोष बढ़ा सकते हैं नए लेबर कोड

जगदीश रत्तनानी

भारत में उत्पादकता कम है, इसलिए नहीं कि भारतीय श्रमिक कम उत्पादक हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें अधिक उत्पादक बनाने के लिए आवश्यक निवेश अक्सर कमजोर या न के बराबर होते हैं। इसके अलावा बिजनेस चेन एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ काम करती है जो श्रम को खर्च करने के रूप में देखती है, जहां एक ढीली नियामक प्रणाली है और जहां श्रम कानून के उल्लंघन से बचना आसान है। लंबे समय से यह तर्क दिया जाता रहा है कि भारत के श्रम कानून-व्यापार, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को कार्यप्रवण होने और देश की विकास गाथा में शामिल होने से रोकते हैं। अब, भारत के 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) में समेकित कर 21 नवंबर को अधिसूचित किया गया है। इसे सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम कहा है जो परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत करता है और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल की नींव रखता है%। कई पर्यवेक्षकों ने इसे भारत में सुधारों की यात्रा में सबसे बड़े कदमों में से एक बताते हुए इसका स्वागत किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में श्रम कानून और वास्तव में कई अन्य कानून, प्रथाएं और परंपराएं पुरानी हो चुकी हैं जिनमें से कई ब्रिटिश राज के जमाने से हैं और पुनरावलोकन के योग्य हैं। सामान्य तौर पर 29 कानूनों की आलोचना की जा रही है। इन कानूनों की समीक्षा एक स्वागतयोग्य कदम होना चाहिए लेकिन इस तरह के विशाल परिवर्तन को कम से कम कुछ आम सहमति के साथ तैयार किया जाए ताकि यह सभी को साथ ले जा सके, विशेष रूप से ट्रेड यूनियंस को।

नई श्रम संहिताओं के सामने पहली बाधा यह है कि यह वास्तविक हितधारक ट्रेड यूनियन्स को सबसे अधिक प्रभावित करेगा और उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। इससे ये बहु-प्रशंसित सुधार उन बदनाम कृषि कानूनों की श्रेणी में आ गए हैं जिन्हें इसी तरह पारित किया गया था और बाद में बड़े पैमाने पर अशांति के बाद वापस लिया गया था। वास्तव में कृषि कानूनों और अब अधिसूचित श्रम संहिताओं के बीच कुछ समानताएं हैं- दोनों को सितंबर, 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया था, दोनों को जोरदार विरोध के बीच पारित किया गया था और दोनों को लाए जा रहे बदलाव के महत्व को न समझते हुए बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया था। उन दिनों सरकार को विश्वास था कि वह कठोर कदम उठाएगी जिससे कृषि कानून पारित हो गए लेकिन बाद में किसानों के जोरदार विरोध से हैरान रह गई और कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। दूसरी ओर, श्रम संहिताओं को प्रभावी ढंग से ठंडे बस्ते में स्थानांतरित कर दिया गया जिसे अब पुनर्जीवित किया गया है। श्रमिक संघ कमजोर हैं इसलिए श्रमिक आंदोलन इतनी आसानी से शुरू नहीं हो सकते हैं; पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि नया प्रयास नकारात्मक नोट पर खुलता है।

कोई भी यह तर्क नहीं दे रहा है कि श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने चाहिए जैसा कि कृषि कानूनों के मामले में तर्क दिया गया था। भारतीय संदर्भ में समस्या कानूनी संहिताओं के बारे में नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने की स्थिति के बारे में है और जो सत्ता के गलियारों, मालिकों और निदेशकों के बोर्ड रूम से स्पष्ट रूप से विपरीत हैं। बाजार की यह वास्तविकता जब एक ऐसी सरकार से मिलती है जिसने श्रमिकों के साथ पूंजी का निर्माण नहीं किया है और जिसे व्यापार लॉबी के पक्ष में काम करने के रूप में देखा जाता है, तो वास्तव में विश्वास गायब हो जाता है। सरकार ने खुद को और तथाकथित सुधारों को उन उपायों के माध्यम से आगे बढ़ाकर नुकसान पहुंचाया है जो भयंकर प्रतिरोध को ट्रिगर करेंगे।

कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभावी होने के बाद ठेकेदारों और प्रतिष्ठानों ने अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया था और वे अपनी सुरक्षा के लिए मीलों पैदल चल कर कंगाल, बदहाल, भूखे-प्यासे अपने गांव पहुंचे थे। ज्यादा जानें उत्पादकता प्रोडक्टिविटी उत्तर प्रदेश समाचार क्षेत्रीय समाचार खेल जगत अपडेट संपादकीय लेख संग्रह राजनीतिक विश्लेषण सेवा युवा समाचार पत्र टैबलेट कविता संग्रह बहरहाल, जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया.

श्रम कानूनों की दिशा कार्यबल को औपचारिक बनाने की ओर है जबकि औपचारिक क्षेत्र में भी कई कमियां हैं। जिस बात का दावा किया जाता है और जिसका वास्तव में अनुभव किया जाता है, उसके बीच काफी अंतर रहता है। बेशक कई क्षेत्रों में मामले निराशाजनक हैं। एक हालिया उदाहरण है भारतीय ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। सेफ इन इंडिया नामक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संस्था की श्रमिकों की सुरक्षा पर सातवीं रिपोर्ट क्रश्ड 2025 में उल्लेख किया गया है कि ऑटोमोटिव सेक्टर सप्लाई चेन में हजारों श्रमिक अपनी उंगलियां (क्रश इंज) खो रहे हैं। 76 प्रतिशत श्रमिकों ने कहा है कि उन्हें सप्ताह में 60 घंटे से अधिक काम करने की सूचना दी गई है। यह ऐप्पल की फॉक्सकॉन समस्या की तरह है - क्या बड़े ब्रांड और सुरक्षा व स्थिरता का दावा करने वाले नेता जब उनके आपूर्तिकर्ता कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो आंखें मूंद लेते हैं।

इनमें कई कार निर्माता नेता हैं। इसे रोकने के लिए कानून में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं लेकिन उन्होंने इस पर अमल क्यों नहीं किया? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नए कानून कैसे और क्यों काम करेंगे? खासकर उन परिस्थितियों में जब कानूनों को उद्योग के अधिक अनुकूल बनाने और जुर्माने के लिए जगह बनाने तथा अपराधों के गैर अपराधीकरण करने की दिशा में है? ध्यान दें कि 22 सितंबर, 2020 को लोकसभा ने चार श्रम संहिताओं में से तीन को पहली बार पारित किया था, उसी दिन सरकार ने सदन में बताया था कि लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मार्च, 2020 में पैदल यात्रा करने वाले लोगों सहित 1.06 करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने गृह-राज्य लौट आए। कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभावी होने के बाद ठेकेदारों और प्रतिष्ठानों ने अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया था और वे अपनी सुरक्षा के लिए मीलों पैदल चल कर कंगाल, बदहाल, भूखे-प्यासे अपने गांव पहुंचे थे। ज्यादा जानें उत्पादकता प्रोडक्टिविटी उत्तर प्रदेश समाचार क्षेत्रीय समाचार खेल जगत अपडेट संपादकीय लेख संग्रह राजनीतिक विश्लेषण सेवा युवा समाचार पत्र टैबलेट कविता संग्रह बहरहाल, जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया तो जो दूसरा सबसे शर्मनाक कृ त्य था कि उद्योग संघों ने श्रम मंत्री से मुलाकात की और श्रम कानूनों की सुरक्षा को हटाने के लिए कहा ताकि व्यवसाय फिर से शुरू हो सके! यह सब हाल ही का इतिहास है। उस समय व्यवसायों के साथ सांठगांठ कर श्रम संहिताओं का जन्म हुआ था। यह देखते हुए कि भारतीय श्रमिक कम शिक्षित, कम जागरूक, कम कुशल, कम समर्थित और इतने कम उत्पादक हैं और अक्सर नौकरी, किसी भी नौकरी के लिए, बेताब होते हैं, यदि हम कार्य प्रणाली पर विचार करें तो देख सकते हैं कि समस्या की जड़ में श्रम शक्ति के प्रति एक निश्चित अवहेलना है जो वैसे भी शोषणकारी प्रथाओं के लिए प्रवृत्त है। भारत में उत्पादकता कम है, इसलिए नहीं कि भारतीय श्रमिक कम उत्पादक हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें अधिक उत्पादक बनाने के लिए आवश्यक निवेश अक्सर कमजोर या न के बराबर होते हैं। इसके अलावा बिजनेस चेन एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ काम करती है जो श्रम को खर्च करने के रूप में देखती है, जहां एक ढीली नियामक प्रणाली है और जहां श्रम कानून के उल्लंघन से बचना आसान है। भारतीय व्यापार क्षेत्र जब श्रम को एक संपत्ति के रूप में देखना और मानना शुरू कर देंगे, उनके विकास और कल्याण में निवेश करेंगे तो अगले आर्बिट में चले जाएंगे एवं श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों को लाल रेखाओं को पार करने के लिए महंगा भुगतान करना होगा। हो सकता है कि नई श्रम संहिताएं हमें वहां तक न ले जाएं।

बंगाल में हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी

शकील अख्तर

अब बंगाल में 44 मुस्लिम विधायक हैं। और हुमायूं कबीर बिहार के सीमांचल की तरह वहां के मुस्लिम बहुल इलाकों से भी मुस्लिम को जिताने की अपील कर रहे हैं। नतीजा बिहार जैसा ही खतरनाक होगा। अपनी जो पार्टी बनाकर वे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें अगर मुसलमान बह गया तो वह अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा। हुमायूं कबीर की तो हो सकता है एक-दो सीटें आ जाएं। 33 साल में पहली बार उत्तर भारत में 6 दिसंबर को शांति रही। कहीं भी पराक्रम दिवस के उग्र प्रदर्शन या बाबरी मस्जिद शहादत का सार्वजनिक गम और गुस्सा प्रकट नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवा दिया। उसी के आर्डर के अनुरूप अयोध्या में जो मस्जिद बनना थी उसका अभी नींव का पत्थर भी नहीं रखा गया। लेकिन बंगाल में इस समय हिन्दू-मुस्लिम राजनीति की जरूरत है। वहां चुनाव हैं। और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से दो बार मोदी वहां कामयाब नहीं हो पाए हैं। विधानसभाओं में सबसे तीखा चुनाव उन्होंने पश्चिम बंगाल में ही लड़ा। महिला मु यमंत्री पर व्यक्तिगत स्तर पर हमला किया। दीदी ओ दीदी इस तरह बोले कि उससे उपहास और अपमान साफ तौर पर प्रतिध्वनित हो रहा था। मगर जनता ने दीदी ओ दीदी को फिर जिता दिया था।

2016 और 2021 दोनों में नाकामयाब होने के बाद इस बार भाजपा अपने सबसे कामयाब हथियार मंदिर-मस्जिद को वहां लेकर आई है। 1992 के इस मंदिर-मस्जिद इशु ने ही उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हटाया था और भाजपा का पहला प्रधानमंत्री बनाया था। 1996 में हुए चुनाव में कांग्रेस हारी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि रहे कुछ ही दिन मगर बीजेपी का हमेशा का एक सपना पूरा हो गया और आगे का रास्ता खुल गया।

अब बंगाल में इसी मंदिर-मस्जिद इशु को जोर-शोर से चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हुमायूं कबीर जो भाजपा के पुराने नेता हैं उसके टिकट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं उनके जरिए बंगाल के मुर्शीदाबाद में एक मस्जिद की नींव का पत्थर रखवाया गया और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। ठीक उसी नक्शे को वहां प्रदर्शित किया गया जैसी गिराए जाने से पहले अयोध्या में मस्जिद थी। यहां यह बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर जो मस्जिद बनना है स्थानीय मुसलमानों ने उसका नाम भी बाबरी मस्जिद नहीं रखा है। मगर वहां से सैंकड़ों किलोमीटर दूर मुर्शीदाबाद बंगाल में चुनाव से ठीक पहले बाबरी मस्जिद उसी स्थापत्य की बनाने की शुरूआत की गई है।

बीजेपी नेताओं के उग्र बयान आप देख रहे होंगे। टीवी की आग लगाऊ डिबेटें भी। यही उद्देश्य था। मुसलमानों को फिर टारगेट पर लिया जाना और हिन्दुओं का ध्रुवीकरण। धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए एक नया चैलेंज। टालने से काम नहीं चलेगा। सबको एकजुट होकर सोचना पड़ेगा। बंगाल की जनता धर्मनिरपेक्ष है। मगर सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। उसे सांप्रदायिकता के जाल में जाने से बचाना होगा। ज्यादा जानें बाबरी मस्जिद क्षेत्रीय समाचार अलर्ट स पादकीय सामग्री मनोरंजन समाचार क्षेत्रीय समाचार कविता संग्रह संपादकीय लेख संग्रह समाचार पत्र सदस्यता ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट विशेष रिपोर्ट सदस्यता रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़े मुद्दों को उठाना होगा। मगर सबसे पहले यह सोचना होगा कि इस सांप्रदायिक मामले को कैसे डिफ्यूज़ करना है। यह दोनों तरफ आग लगाएगा। और जहां हिन्दू-मुसलमान का ध्रुवीकरण हुआ बीजेपी को रास्ता मिल जाएगा। और बीजेपी अगर बंगाल जीत गई तो फिर विपक्ष के लिए कोई विधानसभा सेफ नहीं बचेगी। सोचना मुसलमानों को भी होगा। उनके धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह के नेता जिस तरह जज्बाती सवाल उठा रहे हैं उसके पीछे की मंशा समझना होगी। अभी हुमायूं कबीर से पहले ओवैसी इसी तरह एक नान इशु मुस्लिम कयादत (मुसलमानों का नेता मुसलमान) उठा चुके हैं। परिणाम बिहार में उन्हें तो पांच सीटें मिल गईं मगर मुस्लिम विधायकों की सं या पिछली बार के 19 से घट कर 11 रह गई। जब स्थिति सामान्य रहती है हिन्दू-मुसलमान नहीं होता तो मुस्लिम विधायक भी उचित सं या में चुने जाते हैं। 1985 में जब ओवैसी और भाजपा दोनों की सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी तो वहां 34 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल में ओवैसी की जज्बाती तकरीरों में फंसकर मुसलमानों ने उनके 5 विधायक तो जीता दिए मगर बाकी बिहार में केवल 6 ही मुस्लिम विधायक जीत पाए। अब बंगाल में 44 मुस्लिम विधायक हैं। और हुमायूं कबीर बिहार के सीमांचल की तरह वहां के मुस्लिम बहुल इलाकों से भी मुस्लिम को जिताने की अपील कर रहे हैं। नतीजा बिहार जैसा ही खतरनाक होगा। अपनी जो पार्टी बनाकर वे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें अगर मुसलमान बह गया तो वह अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा। हुमायूं कबीर की तो हो सकता है एक-दो सीटें आ जाएं मगर उसकी कीमत पर भाजपा को सीटें कितनी आएंगी सोच लीजिए। सरकार भी बना सकती है और फिर बुलडोजर से लेकर क्या-क्या आएगा इसे मुसलमानों को सोचना है।

बीजेपी और संघ परिवार तो सामने से उसके खिलाफ है। मगर इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा होता नहीं। उसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब हिन्दुओं में प्रतिक्रिया हो। आज 11 साल के मोदी शासन के बाद भी देश का अधिकांश बहुसं यक उसके साथ नहीं है। 37 प्रतिशत के आसपास ही उसका वोट शेयर डगमगा रहा है। इसलिए खुद सांप्रदायिक इशु उठाने के साथ उसे दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इशु उठाने वाले चाहिए। राजनीति में ओवैसी के बाद उसे हुमायूं कबीर मिल गए। और धार्मिक नेताओं में देश के सबसे बड़ी मौलानाओं के संगठन जमीयत उल उलेमा के मदनी परिवार का साथ। पहले दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम भी बहुत साथ देते थे। मगर इन दिनों कुछ खामोश हैं। अच्छी बात है। लेकिन मदनी परिवार जिसके पास देवबंद जैसा सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षा का केन्द्र है अपनी आपसी लड़ाई में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए फिजूल के इशु उठा रहा है। झगड़ा चाचा-भतीजे का है। कई सालों से संपत्ति और संस्थानों पर कब्जे का। संपत्ति अथाह है। देश विदेश सब जगह फैली हुई और संस्थान हैं जमीयत, देवबंद जैसे प्रतिष्ठित। ऐतिहासिक मस्जिदें। पहले चाचा अरशद मदनी ने एक बिलकुल अप्रासंगिक बात की। मुसलमान के किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने की। यहां सेना की मुस्लिम कर्नल पर सवाल उठ रहे हैं। वहां व्यक्तिगत पदों को जिक्र करके सिवाय फितूर फैलाने के और क्या मिलेगा? इतना पैसा, संसाधन हैं कुछ अपने शिक्षा केन्द्र खोलते। मगर कुछ नहीं। दिल्ली में पांच माइनरटी कालेज हैं। क्रिश्चियन और सिखों के। मुस्लिम का एक भी नहीं। जाकिर हुसैन कालेज का नाम मत लेना। वह मुस्लिम मैनेजमेंट के द्वारा संचालित नहीं है। सरकारी कालेज है। माइनरटी कालेज का मतलब होता है उसके द्वारा संचालित और उसके समुदाय के बच्चों को एडमिशन में विशेष छूट। इसी तरह क्रिश्चियन मशीनरी और सिखों के दिल्ली में कई अच्छे स्कूल हैं। जहां सभी समुदायों के लोग एडमिशन के लिए मारा-मारी करते हैं। मुसलमान भी। लेकिन खुद मुसलमानों का एक भी नहीं। खैर चाचा के बाद भतीजे महमूद मदनी ने और भी गैरजरूरी इशु उठाया जिहाद का। बाद में जगह-जगह वे बताते रहे कि जिहाद का मतलब क्या है? अरे यही मतलब पहले बोल देते तो बीजेपी और गोदी मीडिया को इतना मौका ही नहीं मिलता। संघर्ष है। गलत बात का विरोध है। सबको मालूम है। मगर बीजेपी और संघ तो लोगों को भड़काने के लिए हर चीज के साथ जिहाद लगाती है। महमूद मदनी को क्या जरूरत थी जिहाद करेंगे कहने की। लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आवाज उठाएंगे कई तरह से कह सकते थे। मगर उन्होंने खाली जिहाद ही नहीं कहा, बल्कि अनावश्यक रूप से वंदेमातरम का भी सवाल उठाया। क्या इतनी समझ नहीं है कि ऐसा हर शब्द बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। सोमवार 8 दिसंबर को लोकसभा में बीजेपी सरकार वंदेमातरम पर ही चर्चा करवा रही है। दिन भर होगी। और इसके जरिए बीजेपी मुसलमान को टारगेट करेंगे। ज्यादा जानें बाबरी मस्जिद मनोरंजन समाचार समाचार पत्र सदस्यता ऑनलाइन समाचार सदस्यता आर्थिक समाचार अपडेट उत्तर प्रदेश समाचार युवा सामग्री आर्थिक समाचार राजनीतिक विश्लेषण संपादकीय लेख संग्रह वैसे मु य निशाना तो कांग्रेस रहेगी। वह कांग्रेस जिस का हर स मेलन वंदेमातरम से ही शुरू होता उसे इसी पर घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी की राजनीति ऐसी ही है। नामों की, शब्दों की, प्रतीकों की, झूठे नेरेटिव की। और इसी के आधार पर मुसलमान को हमेशा शक के दायरे में रखने की। कुछ मुसलमान के धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व को सोचना होगा और उससे ज्यादा आम मुसलमान को।

विविध समाचार

जिम ट्रेनर से हुआ पत्नी को प्यार, पति को ठिकाने लगाने के लिए पत्नी ने बुलाए भाड़े के शूटर

अम्बाला ०२/०८ (संवाददाता): हरियाणा के पानीपत के बराड़ा मर्डर केस में बड़ा खुलासा सामने आया है जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में है। इस मामले में सामने आया कि ढाई साल पहले विनोद का मर्डर सुपारी देकर करवाया गया था। जिसमें उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए इस सनसनीखेज वारदात में शामिल थी। पुलिस टीम ने आरोपी सुमित उर्फ बंटू निवासी गोहाना को सेक्टर 11ध्12 की मार्केट से गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार लिया और कई खुलासे किए। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी सुमित उर्फ बंटू ने पुलिस को बताया, साल 2021 में वह पानीपत की एक जिम में ट्रेनिंग देता था। विनोद की पत्नी निधि भी वहां एक्सरसाइज करने के लिए आती थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। विनोद को उन दोनों के बारे में पता चला गया तो उसकी एक दो बार कहासुनी भी हुई। विनोद घर पर अपनी पत्नी निधि के साथ भी झगड़ा करने लगा। बाद में उसने और निधि ने विनोद की एक्सीडेंट में हत्या करवाने की साजिश रची। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया पूछताछ में आरोपी सुमित उर्फ बंटू ने बताया, वह जानकार ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक निवासी भटिंडा से मिला और उसको 10 लाख रुपए नकद और घर का सारा खर्च देने का प्रलोभन देकर वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया। सुमित ने देव सुनार को पंजाब नंबर की एक लोडिंग पिकअप गाड़ी दिलवाई। देव सुनार ने 5 अक्टूबर 2021 को जान से मारने की नीयत से उक्त गाड़ी से सीधी टक्कर मारकर विनोद का एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट मे विनोद की मौत नहीं हुई तो बाद में दोनों ने पिस्तौल से विनोद को मरवाने का प्लान बनाया। देव सुनार की जेल से जमानत करवाई और उसको दोबारा से तैयार कर अवैध हथियार उपलब्ध करवा माफी मांगने के बहाने विनोद बराड़ा के घर भेजा। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार ने घर में घुसकर पिस्तौल से विनोद बराड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी सुमित उर्फ बंटू जेल में बंद देव सुनार के केस और घर पर परिवार का पूरा खर्च खुद दे रहा था। प्लान के अनुसार, निधि मार्च 2024 में अदालत में अपनी गवाही से मुकर गई। पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस ने आरोपी निधि को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सुमित उर्फ बंटू के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकार कर लिया। रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी देव सुनार पानीपत जेल बंद था। पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका था और मामला ट्रायल पर था। इसी बीच बीते दिनों पहले मृतक विनोद बराड़ा के भाई का वॉटसअप पर एक मैसेज आया। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भाई ने मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता होने का संदेह जताया। इसको गंभीरता से लेते हुए सीआईए थ्री प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिसके बाद पुराने राज को फिर से खंगाला गया और गहनता से जांच की गई। जिसके बाद आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

खुशखबरी, सरकार ने बिजली बिल पर मंथली रेंट किया खत्म, केवल यूनिट के देने होंगे पैसे

हरियाणा ०२/०८ (संवाददाता): सरकार ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि जितने यूनिट बिजली खर्च होगी, उतना ही बिल आएगा। इस तरह मंथली मिनिमम चार्ज को समाप्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश में जिन लोगों के घरों में 2 किलोवाट तक के मीटर लगे हुए हैं, उन्हें केवल खर्च की गई यूनिट का ही बिल भरना होगा। इस फैसले से राज्य के करीब साढे 9 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होने वाला है। अब तक उपभोक्ताओं से बिजली विभाग प्रति किलोवाट 115 रुपये मासिक शुल्क के रूप में वसूल रहा था। खर्च हुई यूनिट के पैसों के साथ यह शुल्क जुड़ने से बिल बढ़ जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को कार्ड बांटे। इस योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाने हैं। इससे ये लोग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादक और उपयोगकर्ता दोनों बन सकेंगे। साथ ही, इस पहल से बिजली बिल भी कम होगा। सरकार ने ये भी फैसला किया है कि जो लोग 10 यूनिट से 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, उन्हें सिर्फ 200 रुपए ही देने होंगे। अगर पंजाब की बात करें तो वहां जून के 15 दिनों में बिजली की खपत 2023 की इसी अवधि की तुलना में 43 प्रतिशत बढ़ गई है। इस साल अब तक पंजाब की अधिकतम मांग 15775 मेगावाट हो गई है। पिछले साल जून के पहले 15 दिनों में अधिकतम बिजली की मांग 11309 मेगावाट और धान के मौसम में 23 जून को 15325 मेगावाट थी। पंजाब राज्य में धान की खेती के कारण आने वाले दिनों में अतिरिक्त कृषि भार बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बिजली की स्थिति बेकाबू हो सकती है। एआईपीईएफ ने पहले भी प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मांग की है कि भीषण गर्मी के मौजूदा हालात में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए।

पंजाब में गहराया बिजली संकट, बदला जा सकता है दफ्तरों का समय

पटियाला ०२/०८ (संवाददाता): पंजाब में बढ़ती गर्मी के कारण पारा 44 डिग्री के पार चला गया है तो वहीं अब प्रदेश के लोगों को लंबे बिजली कटों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्ज फेडरेशन ने राज्य में गंभीर हो रही बिजली की उपलब्धता व आपूर्ति की स्थिति पर चिंता जताई है। जिसको लेकर फेडरेशन की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि "पंजाब राज्य में, 2023 के दौरान इसी अवधि की तुलना में 1 से 15 जून, 2024 के बीच बिजली की खपत में 43: की वृद्धि हुई है, जबकि अधिकतम मांग जून 2023 में 11309 मेगावाट से बढ़कर जून 2024 में 15775 मेगावाट हो गई है। पूरे पंजाब राज्य में धान की खेती के कारण जून के अंत तक अतिरिक्त कृषि भार बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बिजली की असहनीय स्थिति हो सकती है।" "महोदय (पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जिक्र करते हुए), एआईपीईएफ आपको भारत का सबसे कुशल और जनहितैषी मुख्यमंत्री मानता है और इसलिए आपसे अनुरोध करता है कि आप हमारे उपरोक्त पत्र में सूचीबद्ध बिजली खपत को नियंत्रित करने की पहल का नेतृत्व करें। हमारी राय में, यदि नीचे दोहराए गए इन कदमों को तुरंत लागू नहीं किया गया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी।" फेडरेशन का कहना है कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो ग्रिड में गड़बड़ी की पूरी संभावना है और लोगों को बिजली से कई दिन वंचित भी रहना पड़ सकता है। फेडरेशन ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बिजली की मांग नियंत्रित करने के लिए कोई कदम न उठाने पर भी चिंता जताई है। इसके साथ ही फेडरेशन ने राज्य में बिजली चोरी पर चिंता जता सरकार को सुझाव दिया है कि बिजली चोरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज करें। बता दें कि 2023 में अधिकतम मांग 11,309 मेगावाट थी। अब वह 15,775 मेगावाट है। धान की रोपाई शुरू होने से बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। राज्य में बिजली की मांग बढ़ने से कट भी लग रहे हैं। यहां तक कि कई जगह तो आठ घंटे तक के कट भी लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि आने वाले समय में लोगों को आठ घंटे से भी ज्यादा लंबे कटों का सामना करना पड़ सकता है और यह संकट कई दिनों तक रहने का भी अनुमान है।

पंजाब में बिजली की खपत में रिकॉर्ड 43 फीसदी की वृद्धि

चंडीगढ़ ०२/०८(संवाददाता): सीवियर हीटवेव के बीच धान का सीजन शुरू होने के चलते पंजाब में जून माह में बिजली की खपत में रिकॉर्ड 43 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। हालात यह हैं कि जून 2023 में जहां बिजली की अधिकतम मांग 11309 मेगावाट दर्ज की गई थी, वहीं इस बार 15775 मेगावाट दर्ज की गई है। इसमें आने वाले दिनों में और वृद्धि होने की आशंका है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने अंदेशा जताया है कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले दिनों में ग्रिड पर लोड बढ़ जाने से पंजाब ही नहीं, पूरे देश में गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। इसे देखते हुए फेडरेशन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से पंजाब में दफ्तरों के समय में बदलाव करते हुए इसे सुबह सात बजे से दोपहर 2 बजे करने का सुझाव दिया है। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे के मुताबिक दफ्तरों के साथ-साथ शापिंग माल व दुकानों को भी शाम सात बजे तक बंद कराया जाना चाहिए। साथ ही उद्योगों पर पीक लोड प्रतिबंध लगने चाहिए। सबसे अहम पहल पर सेंटर पूल से पंजाब के लिए अतिरिक्त 1000 मेगावाट बिजली का प्रबंध किया जाए।

सीएम मान का बड़ा फैसला, डीसी दफ्तरों में शुरू होगी सीएम विंडो

करप्शन होने पर डीसी व एसएसपी पर होगी कार्रवाई

चंडीगढ ०२/०८ (संवाददाता): पंजाब के मुख्यमंत्री ने भगवंत सिंह मान ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि समूह डिप्टी कमिश्नर अपने-अपने जिलों के सरकारी दफ्तरों में आम लोगों को किसी भी तरह की असुविधा और परेशानी के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। यहां डिप्टी कमिश्नरों के साथ मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को साफ-सुथरा, जवाबदेह और प्रभावशाली प्रशासन मुहैया करवाना राज्य सरकार का फर्ज है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ही सबसे कारगर भूमिका निभा सकते हैं जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों में नागरिक केंद्रित सेवाएं निर्विघ्न तौर पर मुहैया करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों का यह फर्ज बनता है कि वे यह यकीनी बनाएं कि उनके सम्बन्धित जिलों के लोगों को सरकारी दफ्तरों का दौरा करते समय किसी किस्म की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस काम में ढील बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी और ऐसी किसी भी लापरवाही के लिए सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर को जवाबदेह बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हर जिले में 'मुख्यमंत्री सहायता केंद्र' स्थापित करने का नवीन प्रयास लेकर आ रही है जिससे लोग इस सहायता केंद्र के द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। भगवंत सिंह मान ने बताया कि 'मुख्यमंत्री सहायता केंद्र' पर एक समर्पित अधिकारी उपस्थित रहेगा जो आम लोगों के रोजमर्रा के प्रशासकीय कामकाज के साथ सम्बन्धित आवेदन-पत्र प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के प्रशासकीय कामों सम्बन्धी आवेदन-पत्र सम्बन्धित विभाग को भेजा जायेगा जिससे काम को तुरंत पूरा किया जा सके। इसी तरह राज्य सरकार से सम्बन्धित कामों को मुख्यमंत्री दफ्तर भेजा जायेगा जिनके हल के लिए इन आवेदन-पत्र को प्रशासनिक विभागों के पास भेजा जायेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 'चीफ मनिस्टर डैशबोर्ड' जिले भर में आम लोगों से उनकी अर्जियाँ और बकाया कामों के बारे फीडबैक लेने के साथ-साथ समूची गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम लोगों के रोजमर्रा के कामों को समयबद्ध और तुरंत पूरा करने को यकीनी बनाऐगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस डैशबोर्ड की नियमित तौर पर निगरानी करेंगे जिससे यह निश्चित बनाया जा सके कि लोगों को अपने आम प्रशासनिक कामकाज के लिए किसी किस्म की असुविधा का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट तौर पर कहा, ''यह सही मायनों में पंजाबियों की सरकार है क्योंकि पंजाब के लोगों ने जबरदस्त जनादेश देकर मुझ में विश्वास जताया था जिससे उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यह यकीनी बनाऐगी कि आम लोगों के सभी कामकाज बिना किसी देरी से किये जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नवीनतम तकनीक को अपनायेगी जिससे सरकारी अधिकारियों का अपने दफ्तरों में उपस्थित होने और लोगों को सेवाएं प्रदान करना निश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज में विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों की शमूलियत को भी बढ़ाया जायेगा जिससे वह प्रशासन और पंजाब सरकार के दफ्तरों के साथ तालमेल करके लोगों के कामों को पूरा कर सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अलग- अलग गाँवों का एक कलस्टर बनाया जायेगा जहाँ प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय विधायक और जन प्रतिनिधियों के साथ इन गाँवों में जाकर लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करेंगे जिससे लोगों को काम के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम होगा क्योंकि 'सरकार तुहाडे द्वार' प्रोग्राम के द्वारा सरकार लोगों के दर पर पहुँच जायेगी और यह यकीनी बनाऐगी कि आम लोगों के कामों को प्रमुखता दी जाये। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से दफ्तरों में पूछताछ और जांच केन्द्रों के रूप में विशेष काउन्टर स्थापित किये जाएंगे, जिससे लोगों को उस दफ्तर का तुरंत पता लग सके कि उनका काम कहाँ से होना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे लोगों के समय और ऊर्जा की बचत होने के साथ-साथ उनके काम को समयबद्ध ढंग के साथ करना यकीनी बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने धान के सीजन के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी मुहैया करवाने का क्रांतिकारी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद किसानों की तरफ से नहरी पानी की योग्य प्रयोग को यकीनी बना कर भूजल के गिर रहे स्तर को रोकना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज भूजल को बचाने की सख्त जरूरत है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मॉनसून के आगामी सीजन में बाढ़ की रोकथाम की तैयारी का जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए वह व्यापक स्तर पर दौरे करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका दौरा घग्गर नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के आसपास होगा।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

राउरकेला, सोमवार 03 अगस्त 2026 पृष्ठ-6

दूसरे पाठ उत्सव में एक ही छत के नीचे संस्कृति, फिटनेस और उत्सव

भुवनेश्वर ०२/०८ (संवाददाता): बारामुंडा-जगमारा नई सड़क पर भारी भीड़ उमड़ी, ज्योंकि भुवनेश्वर ज्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दूसरा पाठ उत्सव ऑर्गनाइज़ किया था। इस मौके पर यह रोड ज्यूज़िक, डांस और मनोरंजन का एक शानदार सेंटर बन गया। सर्दियों की ठंड और सुबह के कोहरे के बावजूद, हज़ारों लोग सुबह से ही वेन्यू पर जमा हो गए, जिससे एक किलोमीटर लंबी सड़क एक रौनक भरे त्योहार में बदल गई। इवेंट का साउंड सिस्टम सुबह करीब 5.30 बजे ज़ोरदार तरीके से बजने लगा, जिससे धीरे-धीरे भीड़ जमा होने लगी।

सुबह 6 बजे तक, पूरी सड़क लोगों से भर गई थी। ऑर्गनाइज़र के मुताबिक, 30,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इसका मज़ा लिया। प्रोग्राम का उद्घाटन भुवनेश्वर की अपराजिता सारंगी ने किया, जो चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं। इस मौके पर एकामरा-भुवनेश्वर के रूरु बाबू सिंह, सेंट्रल रूरु अनंत नारायण जेना, मेयर सुलोचना दास और डिप्टी मेयर मंजुलता कंहार, क्र्स्ष्ट कमिश्नर चंचल राणा और कल्चरल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रामचंद्र राणासिंह के साथ-साथ दूसरे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन और कॉर्पोरेटर भी मौजूद थे। मेहमानों ने स्टेज पर रखे पौधों को पानी दिया, एक साफ़, हरी-भरी और सुंदर राजधानी शहर का संदेश दिया, और दूसरे पाठ उत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया।

उद्घाटन भाषणों के बाद, कल्चरल परफॉर्मेंस ने दर्शकों में जोश भर दिया। प्लेबैक सिंगर दीप्तिरेखा पाधी ने अपने गानों से भीड़ का मन मोह लिया, जिसके बाद जयश्री धल और नारायण दज़ा ने परफॉर्मेंस दी। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद, दर्शक संगीत पर जोश से नाच रहे थे। लोगों को संबोधित करते हुए, इन खास लोगों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शहर को आकर्षक और रहने लायक बनाए रखने के लिए नागरिकों को साफ़, हरा-भरा और जागरूक रहना होगा। उन्होंने बढ़ते प्रदूषण लेवल पर चिंता जताई और लोगों से पर्यावरण बचाने की ज़िज़्मेदारी लेने की अपील की। मेयर दास ने कहा कि आजकल काम पर ध्यान देने वाली लाइफस्टाइल लोगों को मनोरंजन से दूर कर रही है, जिससे स्ट्रेस और हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं। इससे निपटने के लिए, क्र्स्ष्ट मनोरंजन, फिटनेस और सोशल बॉन्डिंग को बढ़ावा देने के लिए तीन ज़ोन में पाठ उत्सव ऑर्गनाइज़ कर रही है।

इस महीने की शुरुआत में मास्टर कैंटीन में हुए पहले पाठ उत्सव के मुकाबले, दूसरा एडिशन ज़्यादा रंगीन था, जिसमें नए गेज़्स और ज़्यादा कल्चरल एज़्टिविटीज़ शामिल थीं। बच्चों के लिए खास इंतज़ाम किए गए थे, जिसमें पज़ल गेज़्स, किड्स किंगडम एज़्टिविटीज़ और ड्राइंग कॉज़्पिटिशन शामिल थे। फेस-पेंटिंग और आर्ट स्टॉल्स पर भारी भीड़ उमड़ी, जबकि महिलाओं के सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स ने सड़क को रंगीन आर्टवर्क से सजाया, जिससे त्योहार का माहौल और भी अच्छा हो गया। इस इवेंट में दो 'भुवनेश्वर गॉट टैलेंट' स्टेज के ज़रिए छिपे हुए लोकल टैलेंट को दिखाने का एक प्लैटफ़ॉर्म भी दिया गया, जहाँ बच्चों, टीनएजर्स और युवाओं ने अपनी जोशीली परफॉर्मेंस से दर्शकों का मन मोह लिया। पारंपरिक डांस और ज़्यूज़िक, मल्लखंब, योग, साइकिलिंग, स्केटिंग, ष्ठ्ठ परफॉर्मेंस, बाघा नाचा, लूडो जैसे बोर्ड गेज़्स और 360-डिग्री कैमरा एज़्सपीरियंस ने पूरे रास्ते विज़िटर्स को बांधे रखा। क्र्स्ष्ट अधिकारियों ने अनाउंस किया कि मौजूदा विंटर सीज़न का फ़ाइनल पाठ उत्सव 1 फरवरी (रविवार) को इंफ़ोसिटी में होगा।

ढेंकनाल के एक स्कूल में पीलिया के दो मामले सामने आए

ढेंकनाल ०२/०८ (संवाददाता): ओडिशा के ढेंकनाल जिले के एक स्कूल में पीलिया के दो मामले सामने आए हैं , जिसके चलते स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने एहतियाती उपायों को तेज कर दिया है। ढेंकनाल के मुज़्य जिला चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अधिकारी (सीडीएम एवं पीएचओ) संजय मोहपात्रा ने कहा कि फिलहाल पीलिया का कोई प्रकोप नहीं है और उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। अभी तक पीलिया का कोई प्रकोप नहीं हुआ है, और हम इसे रोकने के लिए काम कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है। हमें स्कूल में पीलिया के दो मामलों की जानकारी मिली थी, मोहपात्रा ने कहा।उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने स्थिति का आकलन करने के लिए स्कूल का दौरा किया है। उन्होंने कहा, आज मैं जिला शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और सूक्ष्म जीवविज्ञानी के साथ यहां आया हूं। हम यहां से खाद्य और जल के नमूने एकत्र कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि पानी या भोजन में कोई संदूषण तो नहीं है। यह घटनाक्रम खुर्दा जिले के गुरुजंगा गांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) में हाल ही में हुए पीलिया के प्रकोप की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जहां छात्रों के बीच मामलों में वृद्धि ने चिंताएं बढ़ा दी थीं।

उस घटना के बाद से, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सतर्क हो गई है और निगरानी एवं देखरेख बढ़ा दी गई है।अधिकारियों ने कहा कि वे बिश्वनाथपुर आदर्श स्कूल में स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि कोई अतिरिक्त मामले सामने आते हैं तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बाद में 10 जनवरी को, ओडिशा के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉ. नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि उस क्षेत्र में अभी तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है और यदि संज़्या बढ़ती है तो स्थिति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने आगे बताया कि पीलिया के बढ़ते मामलों का संबंध दूषित पानी से है। शुक्रवार को ओडिशा के जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ. नीलकंठ मिश्रा ने कहा, इसका स्रोत पानी है, यानी मल-मूत्र से दूषित पानी, जिसका अर्थ है कि पानी दूषित था और सिस्टम में प्रवेश कर गया।

तीसरी एग्जीज़्यूटिव काउंसिल मीटिंग में 862 प्रोजेज़्ट्स को मंज़ूरी मिली

भुवनेश्वर ०२/०८ (संवाददाता): पंचसखा शिक्षा सेतु की तीसरी एग्जीज़्यूटिव काउंसिल मीटिंग हाल ही में हुई। मीटिंग में, राज्य के 22 जिलों के अलग-अलग स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए 862 प्रोजेज़्ट्स को मंज़ूरी दी गई, जिनका कुल अनुमानित खर्च 12,62,48,373 रुपये था। सभी जिलों में, गंजम को सबसे ज़्यादा मंज़ूरी मिली, जिसके प्रोजेज़्ट्स की कीमत 1.91 करोड़ रुपये थी।मीटिंग की अध्यक्षता काउंसिल की चेयरपर्सन एन तिरुमाला नाइक ने की और कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी, रू×रूश्च नाइक ने एल्युमनाई की लीडरशिप के ज़रिए स्कूल डेवलपमेंट के महत्व पर ज़ोर दिया और इससे जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की। स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए, एल्युमनाई, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों और लोकल कज़्युनिटी ने फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन के तौर पर 4,41,65,582 रुपये का योगदान दिया। इस योगदान के साथ, पंचसखा शिक्षा सेतु ने मैचिंग ग्रांट को दोगुना कर दिया, जिससे कुल 12.62 करोड़ रुपये के खर्च वाले 862 प्रोजेज़्ट प्रपोज़ल को मंज़ूरी मिली। मीटिंग में पंचसखा शिक्षा सेतु की मेंबर सेक्रेटरी और ह्रस्श्क्क की स्क्क्ष्ठ अनन्या दास; एडिशनल सेक्रेटरी दुर्गाप्रसाद महापात्रा; स्पेशल सेक्रेटरी-कम-फाइनेंशियल एडवाइजर शिबाशीष धल; एडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर रमेश चंद्र घड़ेई; ष्ठ।स्श्च की डायरेज़्टर नियति पटनायक; डायरेज़्टर मनोज कुमार पाधी; ष्ठश्चश्च की जॉइंट डायरेज़्टर मनोरमा दास; जॉइंट डायरेज़्टर एसपी पांडा; ऋक्क से जगजीवन पांडा; पंचसखा शिक्षा सेतु की चीफ एग्जीज़्यूटिव ऑफिसर राजलक्ष्मी दाश; स्पेशल प्रोग्राम ऑफिसर मणिप्रसाद मिश्रा; और फाइनेंशियल ऑफिसर इतिश्री महाराणा वगैरह शामिल हुए।

प्राकृतिक वातावरण में ज़्यादा समय बिताएँ-राज्यपाल

भुवनेश्वर ०२/०८ (संवाददाता): बच्चों के लिए खुली जगहों की अहमियत पर ज़ोर देते हुए, गवर्नर हरि बाबू कंभमपति ने उन्हें ज़्यादा स्क्रीन देखने से दूर, कुदरती माहौल में ज़्यादा समय बिताने के लिए हिज़्मत दी और कहा कि ऐसी खुली जगहें कल्पना को बढ़ावा देने, फिजिकल एज़्टिविटी को बढ़ावा देने और इमोशनल सेहत को सपोर्ट करने में मदद करती हैं, साथ ही बाहर के अनुभवों को शेयर करके परिवार के रिश्ते भी मज़बूत करती हैं। गवर्नर ने रविवार को लोक भवन गार्डन और अटल वन में बच्चों से बातचीत की, गार्डन के आम लोगों के लिए खुलने के बाद से यह छोटे विज़िटर्स के साथ उनकी दूसरी मुलाक़ात थी। गवर्नर ने बच्चों से इनफॉर्मल बातचीत की, उन्हें पेन, चिक्की और चॉकलेट गिफ़्ट किए, और जब वे हरे-भरे आस-पास घूम रहे थे, तो उनके साथ समय बिताया। उनकी बातचीत ने लोक भवन के रौनक भरे माहौल में गर्मजोशी और खुशी भर दी, जहाँ परिवार किनारे पर शांत और अच्छी तरह से मेंटेन किए गए गार्डन का मज़ा लेते दिखे। बढ़ते आम लोगों के आने का ज़िक्र करते हुए, कंभमपति ने कहा कि यह ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिखाता है कि लोग खुली, स्वागत करने वाली और आसानी से मिलने वाली जगहों को कितना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि लोक भवन गार्डन को आम लोगों के लिए खोलने का मकसद पज़्लिक संस्थानों को ज़्यादा आसान बनाना और लोगों में शेयर्ड ओनरशिप की भावना को बढ़ावा देना है।

सात ट्रांसजेंडरों ने स्वच्छता को नई परिभाषा दी

कटक ०२/०८ (संवाददाता): कटक ज्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (ष्टरूष्ट) मातागजापुर में अपना फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (स्नस्ञ्जक्क) चला रहा है। हालांकि यह प्लांट साइंटिफिक तरीके से फीकल स्लज मैनेजमेंट और पर्यावरण की सुरक्षा पक्का करने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इस कोशिश के पीछे एक दिलचस्प इंसानी कहानी भी है। स्नस्ञ्जक्क का ऑपरेशन और मेंटेनेंस ओडिशा की व्रत्रड्ढरूस्कीम के तहत काम करने वाले ट्रांसजेंडर कर रहे हैं ङ्क ये वो लोग हैं जिन्हें कभी बदनामी, समाज से अलग-थलग किए जाने और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। आज, वे एक ज़रूरी शहरी सर्विस में सज़्मानित योगदान देने वाले हैं, जो कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज़्म और गर्व के साथ काम कर रहे हैं। सात ट्रांसजेंडर ङ्क सुश्री सीतल बस्तिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सेक्रेटरी; तनुश्री बेहरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट; और सदस्य सिबाने, प्रीतम सिंह, सुमन, टिकी, और रंजन कुमार साहू ङ्क प्लांट के रोज़ाना के काम की रीढ़ हैं। साथ मिलकर, वे एक ऐसी फैसिलिटी के सुचारू कामकाज को पक्का करते हैं जो पूरे शहर से इकट्ठा किए गए मल के कचरे को ट्रीट करती है, जिससे सीधे तौर पर आस-पड़ोस साफ होते हैं और शहरी जीवन सुरक्षित होता है। स्नस्ञ्जक्क की ट्रीटमेंट कैपेसिटी 60 चरूष्ठ है, जिसे ट्रेंड ड्राइवरों और डीस्लजर्स द्वारा ऑपरेट की जाने वाली 13 सेसपूल गाड़ियों से सपोर्ट मिलता है, जिससे कटक में घरों और जगहों के लिए रेगुलर और भरोसेमंद डीस्लजिंग सर्विस मिलती हैं। औसतन, हर महीने कई सौ डीस्लजिंग ट्रिप किए जाते हैं, जिससे मल के कचरे का सुरक्षित और साइंटिफिक ट्रीटमेंट पक्का होता है और एनवायरनमेंट और पज़्लिक हेल्थ के खतरे कम होते हैं।

ट्रेलर की टक्कर से वृद्ध गंभीर

राउरकेला०२/०८ (संवाददाता): सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर थाना अंतर्गत कांधडुड़ा गांव में रविवार की शाम को ट्रेलर की टक्कर से वृद्ध गिर गए। गंभीर अवस्था में उन्हें पहले हेमगिर सरकार अस्पताल फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए सुंदरगढ़ अस्पताल स्थानांतरित किया गया है। कांधडुड़ा गांव निवासी 60 वर्षीय नंदलाल भोई रविवार शाम को पैदल सड़क पर जा रहे थे

आरएसपी में सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए एक किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला आयोजित

राउरकेला०२/०८ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में चल रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता माह-2026 के तहत कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। सयंत्र का सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग अन्य विभागों के सहयोग से आवा जाही करने वालों को सड़क सुरक्षा के नियमों और सावधानियों के बारे में जागरूक कर रहा है। कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। 12 जनवरी को, लगभग 300 कर्मचारियों, अधिकारियों और ठेका श्रमिकों ने आरएसपी कर्मीसमूह की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए एक किलोमीटर से अधिक लंबी सुरक्षा मानव श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ खड़े हुए । मानव श्रृंखला टी एंड आरएम विभाग से एफएम (एम) विभाग तक फैली हुई थी। कार्यपालक निदेशक (वर्क्स), श्री विश्व रंजन पलाई इस अभियान में शामिल हुए और समूह को कार्यस्थल और सड़कों दोनों जगह सुरक्षा मानदंडों का सज़्ती से पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा एक साझा जिज़्मेदारी है और दुर्घटनाओं को रोकने और शून्य क्षति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार जागरूकता, अनुशासन और जिज़्मेदार व्यवहार आवश्यक है। मुज़्य महाप्रबंधक (टी एंड आरएम), श्री के सुन्यानी, महाप्रबंधक (सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग), श्री अबकास बेहेरा, महाप्रबंधक प्रभारी (सीईडी), श्री एस आर पति, महाप्रबंधक प्रभारी (एसएसएम), श्री सी आर मिश्रा ने इस अभियान का नेतृत्व किया। विभागों के विभागीय सुरक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने कार्यक्रम का समन्वय किया। उत्साही प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा के साथ-साथ कार्यस्थल सुरक्षा पर विभिन्न सुरक्षा संदेशों वाले प्लेकार्ड पकड़े हुए थे, जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, सेल फोन के सीमित उपयोग, असुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं, सुरक्षित ड्राइविंग टिप्स, सयंत्र के अंदर गति सीमा, एसओपी, एसएमपी का पालन आदि। यह अभियान सुबह 8.45 बजे से 9.30 बजे तक आयोजित किया गया था, ताकि जनरल शिफ़्ट में संस्कार गेट और मेन गेट दोनों से आने वाले अधिकांश कर्मचारियों को लक्षित किया जा सके।

कार्यपालक निदेशक (वर्क्स) चौक पर नए प्लेट मिल और स्पेशल प्लेट प्लांट द्वारा आयोजित एक अन्य सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में, 400 से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और ठेका श्रमिकों ने मानव श्रृंखला बनाने के लिए सामने आये । यह कार्यक्रम मुज़्य महाप्रबंधक (एनपीएम, एसपीपी और डिजिटलीकरण), श्री आर. के. मुदुली, मुज़्य महाप्रबंधक (सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं), श्री हीरालाल महापात्र के नेतृत्व में विभागाध्यक्ष (एसपीपी), डॉ. पी के पाढ़ी, श्री एन महापात्र, श्री एस सुधाकर, और श्री ए रावत द्वारा आयोजित किया गया था ।

इससे पहले, 8 जनवरी को सीई (एस) विभाग द्वारा कार्यपालक निदेशक (वर्क्स) चौक पर इसी तरह का एक अभियान आयोजित किया गया था। इस अभियान का नेतृत्व महाप्रबंधक प्रभारी (सीईएस),श्री पवन गुप्ता ने किया और इसमें लगभग 150 कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया । 6 जनवरी को आयोजित एक और अभियान में, मुज़्य महाप्रबंधक (प्लेट मिल), श्री एतवा उराँव ने प्लेट मिल रोड पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। 100 से ज़्यादा कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों ने सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर और सुरक्षित और ज़िज़्मेदार सड़क व्यवहार के महत्व को उजागर करने वाले प्लाकार्ड लेकर इस अभियान में योगदान दिया ।